INDIAN POLITY SHORT NOTES

LECTURE 10

Emergency Provisions

(आपात उपबंध)

WHAT IS EMERGENCY?

- Unitary feature of government
- A time period in administration when due to a special reason, federal governments gets replaced by unitary government in a particular area
- Either the existence or Importance of states ends
- Powers gets centralized during emergency

COMPETITION COMMUNITY

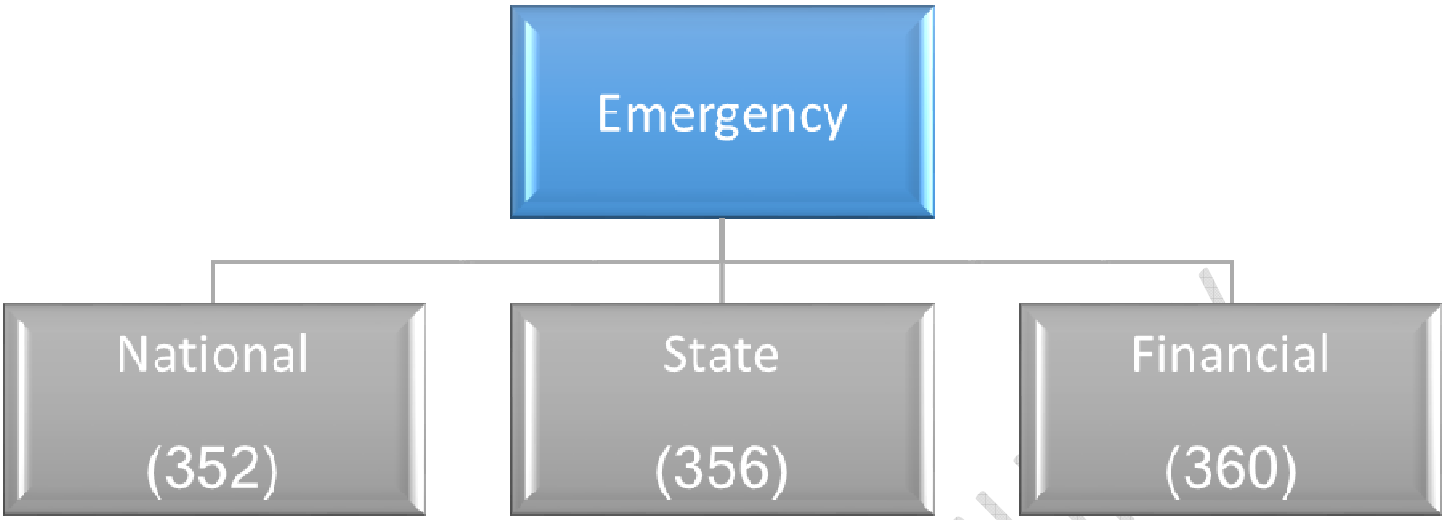

COMPARISION OF NATIONAL AND STATE EMERGENCY

National emergency (352)	State emergency (356)
• Any region or entire nation	• In a particular state(president rule)
• Reason – war, External aggression, Armed Rebellion	• Reason – Failure of constituional machinery of state
• No importance of state	• No existence of state
• Parliament itself frame laws	• Parliament can delegate law making power to president or any authority
• Parliamentary approval – 1 month	• Parliamentary approval – 2 month

National Emergency (352)	State Emergency (356)
• Approval by special majority	• Approval by simple majority
• Validity – indefinite time	• Validity– Maximum 3 years
• Can be removed by President or Loksabha by simple majority	• Can be removed by the President
• Term of Loksabha can be extended at a time by 1 year till indefinite time	• No effect on term of Loksabha
• Fundamental Rights gets suspended	• No effects on fundamental rights
• Imposition – 1962, 1971, 1975	• Imposition – First – 1951- Punjab - Not still in Telangana and CG - Maximum - Manipur

COMP

FINANCIAL EMERGENCY (356)

- Reason – When the financial condition of state is under threat
- State government doesn't dissolve
- Only financial powers of state gets centralized
- Parliamentary approval – 2 months
- Validity – Indefinite time period
- Can be removed by the President
- No such emergency imposed ever in India

COMPETITION COMMUNITY

आपातकाल क्या है?

- भारतीय संविधान का एक एकात्मक तत्व
- प्रशासन में एक ऐसी समयावधि जब, किसी विशेष कारण से, कुछ समय के लिए , किसी क्षेत्र में संघात्मक ढाँचे को स्थागित कर एकात्मक ढांचा लगा दिया जाता है
- राज्य सरकारों का या तो अस्तित्व समाप्त हो जाता है या महत्व
- आपातकाल के दौरान शक्तियाँ केन्द्रीयकृत हो जाती हैं

COMPETI

राष्ट्रीय एवं राज्य आपातकाल का तुलनात्मक अद्ध्ययन

राष्ट्रीय आपातकाल (352)	राज्य आपातकाल (356)
• किसी क्षेत्र या पूरे देश में	• किसी राज्य विशेष में (राष्ट्रपति शासन)
• कारण – युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह	• कारण – संवैधानिक तंत्र की विफलता
• राज्य का महत्व नहीं	• राज्य का अस्तित्व नहीं
• संसद स्वयं नियम बनाती है	• नियम बनाने का अधिकार संसद ,राष्ट्रपति या किसी प्राधिकारी को सौंप सकती है
• 1 माह के भीतर संसद से अनुमोदन आवश्यक	• 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदन आवश्यक
• संसदीय अनुमोदन विशेष बहुमत से	• संसदीय अनुमोदन साधारण बहुमत से
• वैधता – 6 – 6 माह कर के अनंतकाल तक	• वैधता – अधिकतम 3 वर्ष तक
• उद्घोषणा की समाप्ति – राष्ट्रपति द्वारा या लोकसभा के साधारण बहुमत से	• उद्घोषणा की समाप्ति – राष्ट्रपति द्वारा
• लोकसभा का कार्यकाल न्यूनतम 1 वर्ष एवं अधिकतम अनंतकाल तक बढाया जा सकता है | (आपातकाल की समाप्ति के 6 माह से अधिक नहीं)	• लोकसभा के कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं
• मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं	• मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं
• प्रयोग – 3 बार – 1962, 1971, 1975	• प्रयोग – प्रथम बार 1951 में पंजाब में - तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़ में नहीं - सर्वाधिक बार मणिपुर में

वित्तीय आपातकाल(360)

- कारण – किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति या प्रत्यय खतरे में हो
- राज्य सरकार भंग नहीं होती
- केवल वित्तीय शक्तियों का केन्द्रीकरण
- संसदीय अनुमोदन 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से
- वैधता – अनिश्चितकाल तक
- उद्घोषणा की समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा
- भारत में आज तक वितीय आपातकाल कभी नहीं लगा

COMPETITION COMMUNITY